

an>

Title: Need to ensure extension of government sponsored welfare schemes to all the villages in Chhattisgarh.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): भारतवर्ष के जनगणना 2011 के समय छत्तीसगढ़ राज्य के 10 ज़िलेवार कुछ गांव छूट गए हैं, उनके नाम सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण उन गरीब परिवार व कमज़ोर वर्ग हितग्राहियों को केन्द्र, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, स्वास्थ्य योजना, अटल पैशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, बेरोजगारी भत्ता और मातृत्व भत्ता आदि जिस कारण से गांवों के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर जिला बिलासपुर में उसलापुर और हाफा तथा मुंगेली जिला के रामगढ़ सेमरकोना और औराबांधा गांव सम्मिलित हैं जिसे अति आवश्यक रूप से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो भी छत्तीसगढ़ राज्य में छूटे हुए गांव के हितग्राहियों को केन्द्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं का लाभ मिल सके और शासन की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

मैं मांग करता हूं कि पूर्व प्रचलित सन 2002 की जनगणना सूची के आधार पर ही उपरोक्त ग्रामों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए आवश्यक पहल करते हुए अतिशीघ्र निर्देश जारी किए जाने की दया करें।